कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) सारे देश के लिए अभी तक कोई सुव्यवस्थित सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। तथापि, कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में बागवानी के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी परीक्षण आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य में विभिन्न बागवानी वाली फसलों के क्षेत्र कवरेज में प्रक्षेपण शामिल है।

ये परीक्षण अभी तक 10 राज्यों में पूरे किये जा चुके है और अन्य 6-राज्यों में प्रगति पर हैं।

कृषि की उन्नत प्रणालियां

5641. श्री नरेश यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को कृषि की उन्नत प्रणालियों की जानकारी देने के लिए क्या-क्या पद्धतियां अपनाई जा रही है और इस संबंध में वांछित सफलता न मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) देश में विकसित देशों की तुलना में चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, दलहनों और तिलहनों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार प्रयोगशालाओं में विकसित की गई प्रणालियों को कार्यरूप देने और किसानों को तदनुरूप प्रशिक्षण देने के कार्य में निजी और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार): (क) किसानों को कृषि संबंधी उन्नत प्रणालियों की जानकारी देने संबंधी विधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) खेत पर ही मार्गदर्शन तथा सलाह; (2) प्रदर्शन; (3) प्रशिक्षण; (4) अध्ययन दौरे; (5) प्रिंट एवं जन संचार माध्यमों से सहायता; (6) प्रदर्शनियां/कृषि मेले; (7) फार्मर्स फील्ड स्कूल आदि। कृषकों को प्रौद्योगिकी के अन्तरण में उक्त विधियां सामान्यत: उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) जी, हां।

(घ) अनुसंधान में निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल तथा विस्तार में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता अब कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध है। गैर सरकारी संगठन पनघारा तथा कृषि विस्तार कार्यक्रमों में कार्यरत हैं। कृषकों के लिए दीर्घावधि व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है, 81 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन राज्य के कृषि विभागों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

राज्य के विस्तार कार्मिकों एवं किसानों में एकीकृत कीट प्रबंध को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों और राज्य विस्तार कार्मिकों के लिए एक व्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। मौजूदा 26 एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों को सुदृढ़ किया गया है और 4 नए केन्द्र खोले जा रहे हैं। कृषकों के प्रशिक्षण के लिए 1994-95 के दौरान 844 फार्मर्स फील्ड स्कूल खोले गए एवं 1995-96 में 2,200 फार्मर्स फील्ड स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है।

तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चल रही हैं। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम तिलहन कार्यक्रम से संबंधित है एवं राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम दलहन कार्यक्रमों के लिए है। नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। राज्यों के कृषि विभाग के ब्लॉक प्रदर्शनों तथा मिनिकिटों के वितरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाते हैं।

गहन कपास विकास तथा विशेष पटसन विकास कार्यक्रमों के तहत, उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कुल विकसित देशों की तुलना में भारत में फसल उत्पादन

(पैदावार किलोग्राम / हैक्टेयर)

क्रम सं॰	देश	चावल	गेहूं	कदन्न (मोटे अनाज)	दलहन	तिलहन			
						मूंगफली	सोयाबीन	रेपसीड	तिल
1.	भारत	2000	2323	954	556	865	1023	773	333
2.	अमेरिका	6179	2579	5530	1661	2278	2155	1438	उ॰न॰
3.	जापान	4578	3474	3000	1509	1526	1151	1713	533
4.	फ्रांस	4900	6477	6603	4911	उ॰न॰	2589	2838	उ॰न॰
5.	आस्ट्रेलिया	8062	1911	1942	1294	1200	1617	1727	उ॰न॰

(ओशिनिया)

*स्रोतः खाद्य एवं कृषि संगठन, खण्ड 47—1993

उ॰न॰ — उपलब्ध नहीं।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में वृद्धि

5642. **श्रीमती सुषमा स्वराजः**
श्री राम जेठमलानीः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान देश में राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और चावल (धान) की उत्पादन लागत की औसत वार्षिक दर कितनी-कितनी रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लागत की दर में भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में गेहूं और धान की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन लागत कहां-कहां और कितनी-कितनी थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नवीनतम उपलब्ध वर्षों के लिए कुछ राज्यों में धान और गेहूं के उत्पादन की लागत और उसमें वृद्धि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)। धान और गेहूं की उत्पादन लागत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं निकाली जाती है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में उपज के स्तरों में काफी अन्तर है इसलिए उत्पाद की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत भी तदनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

विवरण

नवीनतम उपलब्ध वर्षों के लिए कुछ राज्यों में धान और गेहूं की उत्पादन लागत और उसमें वृद्धि दर्शाने वाला विवरण

फसल	राज्य	उत्पादन लागत रुपए प्रति क्विंटल (सी 2)			1989-90 की तुलना में 1991-92 में उत्पादन लागत में प्रतिशत वृद्धि
		1989-90	1990-91	1991-92	
1	2	3	4	5	6
गेहूं	हरियाणा	135.86	155.44	168.41	23.96
	मध्य प्रदेश	232.11	256.86	317.17	36.65
	पंजाब	164.24	190.79	210.41	28.11